



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 45-2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 1, 2020 (CHAITRA 12, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक प्रथम अप्रैल, 2020

संख्या 26/आ०-1/पं०अ०1/1914/धा० 59/2020.—पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 9/आ०-1/पं०अ०1/1914/धा० 9/2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 के प्रतिनिर्देश से, मैं, शेखर विद्यार्थी, आबकारी आयुक्त, हरियाणा वित्तायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:—

- (1) ये नियम हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।  
(2) ये प्रथम अप्रैल, 2020, से लागू होंगे।
- हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, सारणी में,—  
श्रेणी “अनु०-1खच” तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित श्रेणी तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात्:—

“ अनु०-2खच	भारत में बनी विदेशी मदिरा	नियत	कलक्टर	कलक्टर”;
	की खुदरा दूकानों अर्थात्	फीस		
	अनु०-2 अनुज्ञप्तिधारियों			
	तथा बार अनुज्ञप्तिधारियों			
	अर्थात् अनु०-4 तथा अनु०-5,			
	अनु०-12ग तथा अनु०-12छ			
	द्वारा आयातित विदेशी			
	मदिरा (बी०आई०ओ०) की			
	खुदरा बिक्री			

## 3. उक्त नियमों में, नियम 24 में,—

(i) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(i) प्ररूप अनु०—1 में अनुज्ञप्ति के लिए,—

- (क) ₹1,00,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 10 लाख पूफ लीटर से कम या बराबर है;
- (ख) ₹1,25,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 10 लाख पूफ लीटर से अधिक और 25 लाख पूफ लीटर से कम या उसके बराबर है;
- (ग) ₹1,50,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 25 लाख पूफ लीटर से अधिक और 50 लाख पूफ लीटर से कम या उसके बराबर है;
- (घ) ₹2,00,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 50 लाख पूफ लीटर से अधिक है:

परन्तु ऐसी कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक अनु०—1 लाईसेंस की कुल लाईसेंस फीस का बीस प्रतिशत की प्रतिदेय प्रतिभूति जमा नहीं की जाती है, जो अधिनियम के अधीन जब्त किए जाने अथवा देय किसी राशि या शास्ति के लिए समायोजित किये जाने के लिए दायी होगी।”;

(ii) खण्ड (i-खख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(i-खख) प्ररूप अनु०—4/अनु०—5 में अनुज्ञप्तियों के लिए :—

- (क) 5 स्टार ग्रेडिंग तथा से अधिक के होटलों को ₹ 25,00,000  
प्रदान की गई अनु०—4/अनु०—5 अनुज्ञप्ति :

परन्तु गुरुग्राम—मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स प्लान 2031 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के भीतर भी अनु०—4/अनु०—5 अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाएंगे तथा अनु०—4/अनु०—5 अनुज्ञप्तियाँ उभरते आवासीय नगर क्षेत्रों तथा ऐसे स्थानों में भी प्रदान की जाएगी, जहां हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम ने औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र तथा थीम/विशिष्ट पार्क विकसित किए हैं जैसे कि औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, मानेसर, औद्योगिक आदर्श नगर—क्षेत्र, बावल, औद्योगिक आदर्श नगर—क्षेत्र, रोहतक, औद्योगिक नगर पार्क मानेसर, टेक्नोलोजी पार्क, पंचकुला :

परन्तु यह और कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु०—3) सहित एक मुख्य बार तथा तीन अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसी अनुज्ञप्तियाँ आगे रात—दिन मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी। अनु०—3 अनुज्ञप्ति रखने वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेयों के साथ—साथ होटल कक्षों में रखे रेफ्रीजरेटर्स में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं। यदि अनुज्ञप्तिधारी एक या अधिक अतिरिक्त बिन्दुओं को उप—पट्टे पर देना चाहता है, तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी से 10 लाख रुपये प्रत्येक अतिरिक्त बिन्दु के लिए एक निर्धारित फीस प्रभारित की जाएगी। अनु०—4/अनु०—5 अनुज्ञप्तिधारी बार 12.00 बजे (मध्य रात्रि) तक खुले रख सकते हैं। तदपि, ये अनुज्ञप्त बार गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला जिलों में 01.00 बजे तक खुले रह सकते हैं। बारों के समय को 10 लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर एक घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला जिलों में स्थित इन बार लाईसेंसों का समय और एक घंटे के लिए (अर्थात् 03.00 बजे तक) दस लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर बढ़ाया जा सकता है। मदिरा का विक्रय, जिसमें अनु०—4/अनु०—5 बाजार (बार) के माध्यम से निर्मित आयातित विदेशी मदिरा भी शामिल है, वेट पर 18 प्रतिशत की दर से वेट + 5 प्रतिशत की दर से अधिभार आकर्षित करेगा।

- (ख) 4 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल ₹22,50,000 :

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु०—3) सहित, एक मुख्यबार तथा दो अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को आगे रात—दिन मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अनु०—3 अनुज्ञप्ति रखने वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेयों के साथ—साथ होटल कक्षों में रखे रेफ्रीजरेटर्स में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं :

परन्तु यह और कि राज्य में कहीं भी अवस्थित होटल को भी अस्थायी तौर पर अनु०-4/ अनु०-5 अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी इस शर्त के अधीन कि प्रार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के अन्दर पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार से 4 सितारा तथा इससे उपर का वर्गीकरण प्रस्तुत करेगा तथा असफल होने की स्थिति में अस्थायी अनुज्ञप्ति का बाद में नवीकरण नहीं किया जायेगा। अनुज्ञप्ति अनु०-4/अनु०-5 अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के एक मास के भीतर स्टार रेटिंग के लिए आवेदन करेगा।

(ग) 3 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल के लिए,—

क्रम संख्या	जिले का नाम	अनुज्ञप्ति फीस
1	गुरुग्राम	₹20,00,000
2	फरीदाबाद	₹17,00,000
3	सभी अन्य जिले	₹15,00,000:

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, एक अतिरिक्त बिन्दु तथा कक्ष सर्विस (अनु०-3) सहित, एक मुख्य बार अनुज्ञात किया जाएगा। अनु०-3 अनुज्ञप्ति वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेयों के साथ-साथ होटल कक्षों में रखे रैफरीजरेटों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं :

यह और कि अनु०-4/अनु०-5 अनुज्ञप्ति राज्य के किसी भी स्थान पर अवस्थित तीन सितारा और सितारा होटलों की उपर की श्रेणियों को भी दिया जायेगा। अनु०-4/अनु०-5 अनुज्ञप्ति सरकार द्वारा राज्य में कहीं भी अवस्थित उन होटलों को भी दिए जा सकते हैं, जिनके पास तीन सितारा के बराबर और उससे उपर की श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

परन्तु यह और कि उपरोक्त वर्णित प्रवर्ग (क), (ख) तथा (ग) के ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को उसकी वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 50 प्रतिशत के बराबर एकमुश्त फीस के भुगतान पर बैंकट हाल तथा मुख्य बार से भूमिगत लान, स्रोत सहित अपने परिलक्षित तथा अनुमोदित हालों के तीन (03) तक में किए गए कार्य, पार्टियों, आयोजनों तथा बैठकों में मदिरा परोसने के लिए भी अनुज्ञात किया जाएगा। अनु०-4/अनु०-5 और अनु०-12ग अनुज्ञप्तिधारियों को विहित अनुज्ञप्ति फीस, निर्धारण फीस और परमिट फीस के भुगतान के अधीन रहते हुए अनु०-1खच के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) प्राप्त करने की अनुमति होगी :

परन्तु ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु०-4/अनु०-5 अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।”;

(घ) प्ररूप अनु०-4/अनु०-5 में अनुज्ञप्ति के लिए, खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(क) राजस्व जिला गुरुग्राम के लिए	₹18,00,000
(ख) जिला फरीदाबाद के लिए	₹15,00,000
(ग) गुरुग्राम तथा फरीदाबाद के सिवाए राज्य में सभी अन्य जिलों के लिए	₹10,00,000
(घ) हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा संचालित बार (बारों) के लिए	₹1,50,00,000 की प्रशमन फीस :
(ङ) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा उनके जिमखाना तथा गोल्फ क्लबों में संचालित बार	₹1,50,00,000 की प्रशमन फीस :

परन्तु ₹6.00 लाख की कम्पोजिट प्रतिभूति हरियाणा पर्यटन विभाग तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से कम्पोजिट अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त ली जाएगी:

परन्तु यह और कि कोई भी अनु०-4/अनु०-5 अनुज्ञप्तिधारी जाम की बजाय बोतलों में शराब की, बेहिसाब शराब की, बिना होलोग्राम/आबकारी चिपकने वाला लेबलों की शराब की बिक्री में लिप्त पाया जाता है, तो उसका अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी और परिसरों को दो वर्ष की अवधि के लिए आबकारी अधिनियम के अधीन किसी भी अनुज्ञप्ति को रखने के लिए मना कर दिया जायेगा।

- (iii) (क) खण्ड (ii) में, "₹70,00,000" अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, "₹1,00,00,000" अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) खण्ड (ii-क) का लोप कर दिया जायेगा।
- (ग) खण्ड (ii-ख) का लोप कर दिया जायेगा।
- (iv) खण्ड (ii-ख) के पश्चात, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु प्रस्तावित बाटलिंग प्लांट को आशय का कोई नया पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक राज्य में मौजूदा आसवनी की स्थापित उत्पादन क्षमता का 90 प्रतिशत एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल का वास्तविक उपयोग न हो जाए। आगे, प्रस्तावित बाटलिंग प्लांट के लिए आशय का कोई भी पत्र वर्ष 2020-21 में पुनर्विधिमार्गकरण नहीं किया जाएगा, यदि आवेदक अपने आशय पत्र के उपबन्धों के अधीन निर्धारित समय के भीतर संयंत्र स्थापित करने में अफसल रहता है।

- (v) खण्ड (ii-ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ii-ग) भारत में बनी विदेशी स्पिरिट पर बाटलिंग फीस निम्न अनुसार उदगृहीत की जाएगी:-

		राज्य के भीतर आपूर्ति के लिए	भारत के भीतर राज्य से बाहर आपूर्ति के लिए	भारत के बाहर निर्यात
(क)	उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग डी-2 अनुज्ञप्ति के लिए	₹15.00 /- प्रति प्रूफ लीटर	₹7.50 /- प्रति प्रूफ लीटर	शून्य
(ख)	उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग प्लांट बाटलिंग के लिए	₹20.00 /- प्रति प्रूफ लीटर	₹10.00 /- प्रति प्रूफ लीटर	शून्य
(ग)	उपरोक्त (क) तथा (ख) में न आने वाले ब्राण्ड की बाटलिंग के लिए तथा जहाँ फेचार्ज फीस उदगृहीत नहीं की गई है	₹22.00 /- प्रति प्रूफ लीटर	₹11.00 /- प्रति प्रूफ लीटर	शून्य
(घ)	बुअरज के द्वारा बीयर की बाटलिंग के लिए	₹8.00 /- प्रति प्रूफ लीटर	₹4.00 /- प्रति प्रूफ लीटर	शून्य

परन्तु बाटलिंग फीस, निर्यात के लिए मदिरा के साथ साथ स्थानीय उपभोग के लिए भी मदिरा पर उदगृहीत होगी, यदि कोई भी फेचार्ज फीस उदगृहीत नहीं की गई है।";

- (vi) खण्ड (iv) में, अन्त में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु प्ररूप अनु०-12 क में अनुज्ञप्ति उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा एक व्यक्ति को एक दिन के दौरान शराब परोसने के लिए कब्जा सीमा से अधिक दिया जाएगा। निम्नलिखित श्रेणियाँ अनु०-12क अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए ऑनलाईन आवेदन करेंगी:-

- बैंकट हाल, फार्म हाउस, सामुदायिक केन्द्रों, सार्वजनिक पार्कों/हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, समारोह वाली धर्मशालाओं, एकत्रित होने के लिए तथा विवाह पार्टियों में शराब परोसने के लिए।
- एक विशिष्ट दिन पर समारोह की मेजबानी के लिए अस्थायी आधार पर अपने अनुज्ञप्त परिसर के बाहर शराब परोसने के लिए अनुज्ञप्त होटलों, रेस्टोरेंटों तथा क्लबों के लिए।
- कब्जे की सीमा से अधिक, व्यक्तिगत के लिए एक दिन हेतु निजी स्थान पर शराब परोसने के लिए।

वाणिज्यिक स्थानों जैसे बैंकट हाल, पार्टी हॉल/लॉन वाले होटलों को सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय में आबकारी विभाग में अनिवार्य रूप से

पंजीकरण करवाना होगा। पार्टी हॉल/लॉन वाले बैंकट हॉल और होटलों का वार्षिक पंजीकरण शुल्क निम्नानुसार होगा :-

क्रम संख्या	बैंकट हॉल/होटल का अवस्थान	वार्षिक पंजीकरण फीस
1	गुरुग्राम तथा फरीदाबाद की कारपोरेशन सीमा	₹40,000
2	अम्बाला, हिसार, करनाल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर की कारपोरेशन सीमा	₹25,000
3	शेष जिला हैडक्वार्टर शहरों की परिषद/समिति सीमा	₹15,000
4	जिले की नगरपालिका सीमा के बाहर राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग पर पडने वाले बैंकट हाल/होटलों (आबकारी नीति तथा आबकारी नियमों के उपबन्धों के अधीन)	₹10,000
5	ग्रामीण क्षेत्रों में पडने वाले बैंकट हॉल(उपरोक्त श्रेणी 4 में विनिर्दिष्ट से भिन्न)	₹5,000

अनु०-12क अनुज्ञप्ति के लिए फीस ढांचा निम्नानुसार होगा :-

क्रम संख्या	बैंकट हॉल/होटल का अवस्थान	वार्षिक पंजीकरण फीस
(i)	वाणिज्यिक स्थानों पर मदिरा परोसने वाले व्यक्ति के लिए	₹7,500 प्रतिदिन प्रति समारोह
(ii)	कब्जा सीमा से बाहर निजी स्थान पर व्यक्तिगत हेतु शराब परोसने के लिए	₹1,000 प्रतिदिन प्रति समारोह

सभी वाणिज्यिक स्थानों में अनु०-12 क अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन में प्रबन्धक के ब्यौरे अर्थात् नाम तथा शैली, जी.एस.टिन तथा मेहमानों की लगभग संख्या तथा मदिरा की मात्रा वर्णित होगी।”;

परन्तु यह और कि यदि कोई भी बैंकट हॉल/होटल वैध अनु०-12क अनुज्ञप्ति के बिना शराब परोसता पाया जाता है, तो प्रथम अपराध के लिए ₹50,000/-की शास्ति लगाई जाएगी, द्वितीय और तृतीय अपराध के लिए ₹1,50,000/-की शास्ति लगाई जाएगी। आगे पश्चातवर्ती उल्लंघन की दशा में, ऐसे बैंकट हाल/होटल को एक वर्ष की अवधि के लिए कोई भी आबकारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विवर्जित कर दिया जायेगा।

(vii) खण्ड (iv-ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv-ख)प्ररूप अनु०-12ग में अनुज्ञप्ति के लिए,-

(क)	राजस्व जिला गुरुग्राम के लिए	₹18,00,000 /-
(ख)	जिला फरीदाबाद के लिए	₹15,00,000 /-
(ग)	गुरुग्राम तथा फरीदाबाद के सिवाए राज्य के सभी अन्य जिले	₹10,00,000 /-

परन्तु अनु०-12ग अनुज्ञप्तियों, इसके अधीन यथा उपबन्धित के सिवाय, जिला मुख्यालय शहरों में स्थित इस प्रयोजन के लिए गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा विहित मानदण्डों तथा शर्तों को पूरा करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना और सुविधाओं का स्तर रखने वाले ख्यातिप्राप्त क्लबों को प्रदान की जाएगी। अनु०-12ग रखने वाला क्लब अनु०-4/ अनु०-5 को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का हकदार होगा, जिसमें 3 स्टार की ग्रेडिंग होगी। इस अनुज्ञप्ति की फीस बीस लाख रुपये होगी:

परन्तु यह और कि जिला मुख्यालय के शहरों में आवासीय कॉलोमिनियम के लिए अनु०-12ग के रूप में अनुज्ञप्ति की अनुमति अनुज्ञात की जाएगी। मुख्य बार एल-4/एल-5 अनुज्ञप्ति के बराबर होगा, जब कॉलोमिनियम के अन्दर कोई अतिरिक्त मिनी क्लब प्रत्येक ऐसे अतिरिक्त मिनी क्लब के लिए अपने मुख्य बार की अनुज्ञप्ति फीस के 20 प्रतिशत की दर से अनुज्ञप्ति भी प्राप्त करेगा। यह इस शर्त के अधीन होगा कि केवल कॉलोमिनियम के निवासियों को इस सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी :

परन्तु यह और कि अनु०-12ग अनुज्ञप्ति सरहिन्द क्लब, अम्बाला को प्रदान किए जाने पर, सेना के अधिकारी को सी.एस.डी. कैंटीन के माध्यम से अपने कोटा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी जबकि नागरिक सदस्य सी.एस.डी. कैंटीन के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली शराब के लिए हकदार नहीं होंगे:

परन्तु यह और कि कोई भी अनु०-12ग अनुज्ञप्तिधारी जाम की बजाय बोतलों में शराब की, बेहिसाब शराब की, बिना होलोग्राम/आबकारी चिपकने वाले लेबलों की शराब की बिक्री में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति तुरन्त रद्द कर दी जाएगी और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी और परिसरों को दो साल की अवधि के लिए आबकारी अधिनियम के अधीन किसी भी अनुज्ञप्ति को रखने के लिए विवर्जित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि पाँच लाख रुपये की प्रतिदेय प्रतिभूति अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु०-12ग अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।”;

(viii) खण्ड (iv-ग) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

(iv-ग) प्ररूप अनु०-12गग में अनुज्ञप्ति के लिए:-

(क)	9 होल तक क्षमता सहित गोल्फ क्लब (दो विक्रय बिन्दुओं सहित)	₹30,00,000
(ख)	18 होल तक क्षमता सहित गोल्फ क्लब (तीन विक्रय बिन्दुओं सहित)	₹50,00,000:

परन्तु शराब परोसने के लिए अनुज्ञप्ति केवल 9 होल या उससे अधिक सुविधाओं वाले गोल्फ क्लबों को प्रदान की जाएगी तथा उन्हें किसी भी होटल या किसी भी प्रकार के बार अनुज्ञप्ति के साथ अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अनु०-12गग क्लब बार के अनुज्ञप्तिधारी 12.00 (मध्य रात्रि) बजे तक खुले रख सकते हैं। तथापि, ये अनुज्ञप्त बार गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला जिलों में 01.00 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। दस लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर बारों के समय को एक घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला जिलों में स्थित इन बार लाईसैंसों का समय, एक और घंटे के लिए (अर्थात् यानि 03.00 बजे तक) दस लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर बढ़ाया जा सकता है।

**टिप्पण 1** पहले से ही अनुज्ञात उपरोक्त दिए गए किसी भी अतिरिक्त स्थल को प्रत्येक ऐसे स्थल के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की 20 प्रतिशत फीस के समान अदायगी पर चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा प्रति अनुज्ञप्ति अधिकतम तीन अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति दी जायेगी।

**टिप्पण 2** हरियाणा पर्यटन तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा उनके अपने जिमखाना तथा गोल्फ क्लबों में बार चलाने की दशा में, उन्हें ऐसे प्रत्येक स्थल के लिए एक लाख रुपये के बराबर फीस के भुगतान पर चलाने की अनुमति दी जाएगी:

परन्तु ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु०-12गग क्लब बार अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।”;

(ix) खण्ड (v) में, खण्ड (i) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :-

“(v) (i) देसी मदिरा (अनु०-13) के थोक बाजार के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नलिखित प्रकार से होगी:-

- (1) ₹30.00 लाख यदि आबकारी जिले में देशी शराब का वार्षिक कोटा 25 लाख पूफ लीटर के बराबर या उससे कम है।
- (2) ₹35 लाख यदि आबकारी जिले में देशी शराब का वार्षिक कोटा 25 लाख पूफ लीटर से अधिक या 50 लाख पूफ लीटर से कम है।
- (3) ₹40 लाख यदि आबकारी जिले में देशी शराब का वार्षिक कोटा 50 लाख पूफ लीटर के बराबर या उससे अधिक है।

अनुज्ञप्तिधारी से जिले में ₹10.00 लाख प्रति अनु०-13 की प्रतिदेय प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी।”;

- (x) खण्ड (i-ग) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“(i-ग) प्ररूप अनु०-1ख में अनुज्ञप्ति के लिए ₹60,00,000;”;

- (xi) खण्ड (i-ड) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“(i-ड) प्ररूप अनु०-1ख में अनुज्ञप्ति के लिए,-

1.	नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहाँ वर्ष 2019-2020 में अनु०-1ख से वार्षिक बिक्री 50 लाख प्रूफ लीटर के बराबर या उससे कम है।	₹50,00,000;”;
2	यदि वर्ष 2019-2020 में, अनु०-1ख से वार्षिक बिक्री के मामले में, 50 लाख प्रूफ लीटर से अधिक है	₹1,00,00,000;”;

- (xii) खण्ड (i-डडडड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(i-डडडड) प्ररूप अनु०-1खच में अनुज्ञप्ति के लिए,-

- (क) अनु०-1खच के लिए अनुज्ञप्ति फीस ₹1,00,00,000/-होगी;
- (ख) विभागीय पोर्टल पर आवेदन पत्र को ऑन-लाईन आमन्त्रित करके अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी;
- (ग) आवेदक को केवल एक आवेदन करने की अनुमति होगी। आवेदक, हरियाणा राज्य या किसी अन्य राज्य में कोई थोक अनुज्ञप्तिधारी, या कोई प्रोपराटर फर्म या कोई भागीदारी फर्म या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन पंजीकृत कोई कम्पनी या सुसंगत विधि के अधीन पंजीकृत कोई सोसाइटी या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अधीन पंजीकृत कोई फर्म होगी।
- (घ) आवेदक ₹2,00,000 की आवेदन फीस जमा करेगा। आवेदन फीस गैर वापसीयोग्य और गैर समायोज्य होगी। आवेदन के साथ ₹10,00,000 की प्रतिभूति राशि भी होगी। आवेदन, आवेदक की पहचान स्थापित करने वाले दस्तावेजों के साथ होगा। सभी व्यक्तियों के पहचान प्रमाण, जैसे प्रोप्राइटर, सभी भागीदार, निदेशक और प्राधिकृत व्यक्ति, यदि कोई भी ऐसा प्राधिकृत है, तो आवेदन के साथ ही ऑन-लाईन अपलोड किया जाना चाहिए।
- (ङ) आबकारी विधि के उपबन्धों के अनुसार जो सभी आवेदन सही पाए गए हैं, को पात्र माना जाएगा। विभाग अपनी विभागीय वेबसाइट पर पात्र आवेदकों की सूची प्रकाशित करेगा और, इसे उसके लाईसैंस के आबंटन की तिथि माना जाएगा। अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति के प्रदान करने के दिन से शुरू होने वाली अवधि या प्रथम अप्रैल, 2020, जो भी बाद में हो, के लिए वैध होगी।
- (च) पात्र आवेदक लाईसैंस फीस और अतिरिक्त लाईसैंस फीस के 25 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि, यदि लागू हो, एक सप्ताह के भीतर या आबंटन की तिथि के नोटिस में निर्धारित ऐसे समय के भीतर जमा करेगा। अग्रिम राशि प्रतिभूति राशि के भुगतान के लिए समायोज्य होगी।
- (छ) निम्नलिखित मामलों में आवेदक की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी:-
- यदि आवेदक अपने आवेदन में कोई गलत या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करता है;
  - यदि आवेदक किसी भी कदाचार में लिप्त होने का दोषी पाया जाता है;
  - यदि सफल आवेदक आबंटन के सात दिन के भीतर प्रतिभूति राशि की किस्त जमा करने में विफल रहता है;
  - यदि सफल आवेदक उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जो उसे आबंटन के सात दिन के भीतर विभाग को प्रस्तुत करने आवश्यक है या किसी अन्य कारण के लिए जैसा कि आबकारी आयुक्त उचित समझे।
- (ज) यदि विभाग मानता है कि पर्याप्त संख्या में पात्र आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वह अधिक आवेदनों को आमन्त्रित करके आबंटन का एक और दौर शुरू करेगा।



- (झ) यदि अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो आबकारी तथा कराधान आयुक्त सभी अनुज्ञप्तिधारियों का कोटा समान मात्रा में कम कर सकता है ताकि सभी अनुज्ञप्तिधारियों का कुल न्यूनतम कोटा राज्य की आवश्यकता के अनुरूप हो।
- (ण) पात्र आवेदक अन्य सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा, जो नोटिस, हिदायत और पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित हैं।
- (ट) आवेदक को अपनी प्रतिभूति राशि जमा करने के बाद अनुज्ञप्तिधारी माना जायेगा।
- (ठ) सफल आवेदक अनुज्ञप्ति फीस और अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस, यदि लागू हो, तो अनुज्ञप्ति फीस और अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के दस प्रतिशत के बराबर प्रत्येक, यदि लागू हो, तो आठ मासिक किश्तों में भुगतान करेगा। अनुज्ञप्ति फीस का शेष भाग पच्चीस प्रतिशत प्रतिभूति राशि से समायोजित किया जायेगा। अनुज्ञप्ति फीस की प्रत्येक किश्त अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 तक शुरू होने वाले प्रत्येक महीने की 20 तिथि तक देय होगी। प्रतिभूति से बकाया राशि, यदि कोई है, अनुज्ञप्तिधारी की ओर देय किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद वापस कर दी जाएगी। भारत में बनी विदेशी मदिरा और देशी मदिरा के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस जमा करने में देरी की अवधि के लिए ब्याज लगाया जाएगा।
- (ड) अनु०-1खच अनुज्ञप्ति के लिए न्यूनतम कोटा निम्नानुसार नियत किया जायेगा:-

(i) विस्की, स्कॉच, रम, वोदका, जिन, ब्रांडी आदि	10000 पेटियों
(ii) बीयर	7000 पेटियों
(iii) वाईन, साईडर, लीकर आदि	3000 पेटियों

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय वर्ष में उपर बताए अनुसार न्यूनतम कोटा उठाना होगा। न्यूनतम कोटा उठाने में विफलता की दशा में विस्की और वाईन के मामले में ₹3000 प्रति पेटि शास्ति जो उपरोक्त (i), (iii) में दर्शायी गई है, तथा ₹1500 प्रति पेटि बीयर के मामले में उपरोक्त (ii) के अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाएगी। तिमाही के आधार पर कोटे की निगरानी की जायेगी। संचयी आधार पर गणना की गई प्रत्येक तिमाही के अन्त में उठाए गए कोटे की कम मात्रा के लिए शास्ति उद्ग्रहणीय होगी। तिमाही में दंडित किए गए कोटे की कमी के मामले में, उसी कोटे को बाद के किसी भी तिमाहियों में फिर से दंडित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक खण्ड का वार्षिक कोटा 25 प्रतिशत होगा। वाईन के कोटे को विस्की के सेगमेंट में किसी अतिरिक्त फीस के बिना गणना किए जाने के अनुरोध पर अन्तरित करने की अनुमति दी जायेगी;

- (ड) अनुज्ञप्तिधारी किसी अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के बिना अतिरिक्त कोटे का भी हकदार होगा, जो न्यूनतम कोटे का 50 प्रतिशत होगा। यह उसके न्यूनतम कोटा को समाप्त करने के बाद उपलब्ध होगा।
- (ड) निर्धारण फीस तथा परमिट फीस निम्न प्रकार से उद्गृहीत की जायेगी:-

मदिरा का प्रकार	निर्धारण फीस	परमिट फीस
विस्की	₹200 प्रति प्रूफ लिटर	₹25 प्रति प्रूफ लिटर
वाईन	₹200 प्रति बल्क लिटर	₹25 प्रति बल्क लिटर
बीयर	₹70 प्रति बल्क लिटर	₹10 प्रति बल्क लिटर

- (त) आयातित विदेशी मदिरा पर वैट 5 प्रतिशत के अधिभार के साथ 10 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा
- (थ) ₹5,000 प्रति बोतल की शास्ति, शामिल बोतलों के आकार को ध्यान में रखे बिना, अनु०-1खच के परिसरों, या अनु०-1, अनु०-2, अनु०-4 तथा अनु०-5, अनु०-12ग, अनु०-12छ, अनु०-10ख इत्यादि जैसे किसी अन्य परिसरों पर पाई गई विस्की और वाईन की हर बेहिसाब बोतल पर लगाई जाएगी। शास्ति उन अनुज्ञप्तिधारियों पर लगाई जायेगी जिसके परिसर पर शराब पाई गई है। बीयर के मामले में शास्ति ₹3,000 प्रति बोतल, बोतल के आकार को ध्यान में रखे बिना लगाई जायेगी।
- (द) आयातित विदेशी मदिरा (बी०आई०ओ०) की विस्की और वाईन के स्टॉक पर, ₹7,000 प्रति बोतल की शास्ति, किसी भी अनुज्ञप्त परिसर पर कम पाये जाने पर, लगाई जाएगी। बीयर के मामले में, प्रति बोतल ₹3,000 की शास्ति लगाई जायेगी।



- (घ) वर्ष 2019-2020 के लिए अनु०-1खच का निवर्तमान अनुज्ञप्तिधारी वर्ष 2020-2021 के लिए आने वाले किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को दिनांक 31 मार्च, 2020 को आयायाति विदेशी मदिरा का बचा हुआ स्टॉक अन्तरित कर सकता है। विस्की, स्कॉच, रम, वोदका, जिन और ब्रांडी इत्यादि के लिए ₹120 प्रति प्रूफ लीटर की दर से और वाईन के लिए ₹120 प्रति बल्क लीटर और बीयर पर ₹50 प्रति बल्क लीटर की दर से अन्तरण फीस भी लगाई जायेगी ;
- (xiii) खण्ड (i-डडडड) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :-
- “(i-डडडडड) प्ररूप अनु०-2खच में अनुज्ञप्ति के लिए,-
- (क) प्ररूप अनु०-2खच में अनुज्ञप्ति निर्धारित फीस पर दी जाएगी;
- (ख) प्ररूप अनु०-2खच में अनुज्ञप्ति निम्नानुसार दी जाएगी :-
- (i) प्ररूप अनु०-2खच में अनुज्ञप्ति एक निश्चित मूल्य पर भारत में बनी विदेशी मदिरा अर्थात् अनु०-2 की कुछ निश्चित खुदरा दूकानों को दी जाएगी, जो कि आयातित विदेशी शराब (बी०आई०ओ०) के लिए ठेके की क्षमता के अनुसार निश्चित की जायेगी। भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु०-2) के ऐसे खुदरा ठेकों की अनुज्ञप्ति फीस आबकारी व्यवस्था में अलग से दिखाई जाएगी और यह ठेके की निविदा राशि से अधिक होगी। प्रत्येक ऐसे अनु०-2खच को विस्की, बीयर और वाईन की पेटियों की शर्त पर आयातित विदेशी शराब(बी०आई०ओ०) का न्यूनतम कोटा प्रदान किया जायेगा। ऐसे अनु०-2खच का न्यूनतम कोटा आबकारी व्यवस्था में दर्शाया जायेगा। अनु०-2खच की प्रतिभूति और अनुज्ञप्ति फीस उन नियमों के अनुसार वसूल की जायेगी जो खुदरा दूकानों की प्रतिभूति और अनुज्ञप्ति फीस अर्थात् अनु०-2 और अनु०-12क की वसूली के लिए लागू हैं। अनु०-2 तथा अनु०-14क के खुदरा ठेकों के मामले में कोटा उठाने तथा कोटा न उठाने के लिए शास्ति के उपबन्ध, इन अनु०-2खच अनुज्ञप्तियों के लिए यथा आवश्यक प्रवर्तन लागू होंगे। तथापि, विस्की और वाईन के लिए कम कोटा उठाने के लिए शास्ति ₹5,000 प्रति पेट्टी होगी तथा बीयर के लिए ₹2000 प्रति पेट्टी होगी।
- (ii) प्ररूप अनु०-2खच में अनुज्ञप्ति राज्य की भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु०-2) के खुदरा ठेकों को भी निम्नलिखित अनुज्ञप्ति फीस तथा कोटे पर दिया जायेगा जो उपर वर्णित (i) में निर्धारित नहीं हैं, के लिए निम्नलिखित फीस और कोटा:-
- (क) 1000 पेट्टियों के न्यूनतम कोटा के लिए अनुज्ञप्ति फीस ₹5,00,000, जिसमें विस्की की 500 पेट्टियों, बीयर की 350 पेट्टियों तथा वाईन की 150 पेट्टियों शामिल होंगी।
- (ख) अनु०-2खच की अनुज्ञप्ति फीस अग्रिम तौर पर एकमुश्त में अदा की जाएगी।
- अनु०-2खच अनुज्ञप्तिधारियों के दोनों उपरोक्त वर्णित प्रवर्ग किसी अतिरिक्त फीस के बिना अपने न्यूनतम कोटा के 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त कोटा के हकदार होंगे। आयातित विदेशी मदिरा (बी०आई०ओ०) का कोटा भारत में बनी विदेशी मदिरा के कोटे से अलग होगा।
- (iii) प्ररूप अनु०-2खच में अनुज्ञप्ति, अनु०-4 तथा अनु०-5, अनु०-12ग तथा अनु०-12छ एकमुश्त देय ₹5,00,000 की नियत फीस पर दी जाएगी। निर्धारण फीस और परमिट फीस की दरें निम्नलिखित प्रकार से होंगी :-

मदिरा का प्रकार	निर्धारण फीस	परमिट फीस
विस्की	₹75 प्रति प्रूफ लीटर	₹25 प्रति प्रूफ लीटर
वाईन	₹75 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹40 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

## 3. उक्त नियमों में, नियम 27-क में,—

(i) उप-नियम (1) में, खण्ड (iii) तथा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

“(iii) शापिंग माल में स्थित नजदीकी अनु०-2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त ₹25,00,000 प्ररूप अनु०-10ख में अनुज्ञप्ति के लिए फीस

परन्तु अनु०-10ख अनुज्ञप्तिधारियों को एकमुश्त भुगतानयोग्य ₹2,00,000 की नियत फीस के भुगतान के अधीन रहते हुए प्ररूप अनु०-1ख में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद आयातित विदेशी शराब (बी०आई०ओ०) खरीदने की अनुमति होगी। मूल्यांकन फीस तथा परमिट फीस की दरें निम्नलिखित होंगी :—

मदिरा का प्रकार	निर्धारण फीस	परमिट फीस
विस्की	₹75 प्रति प्रूफ लीटर	₹25 प्रति प्रूफ लीटर
वाईन	₹75 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹40 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर;”

(iv) प्ररूप अनु०-10ग में अनुज्ञप्ति के लिए ₹10,00,000”।

## 4. उक्त नियमों में, नियम 31क में, “325” अंको के स्थान पर, “410” अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

## 5. उक्त नियमों में, नियम 36-क में,—

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(1) ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकों का आबंटन, जोन में बांटा जाएगा। जोन का कमाण्ड क्षेत्र, आबकारी व्यवस्था में जोन के लिए भौगोलिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा। आबकारी व्यवस्था के भाग के रूप में ऐसे कमाण्ड क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) सक्षम प्राधिकारी होगा। शहरी क्षेत्रों में ठेकों का स्थान नियत किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी को उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) के अनुमोदन के अध्वधीन ग्रामीण क्षेत्रों में जोन के कमाण्ड क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर अपना ठेका रखने की स्वतन्त्रता होगी। एक जोन में पूर्व निर्धारित स्थानों सहित शहरी क्षेत्रों में दो खुदरा ठेके शामिल होंगे; ग्रामीण क्षेत्रों में दो खुदरा ठेके तथा अनुज्ञप्तिधारी को अपने कमाण्ड क्षेत्र में कहीं भी इन ठेकों की लोकेशन का निर्णय करने में सुगमता होगी। अनुज्ञप्तिधारी को कुल दो खुदरा ठेकों की सम्पूर्ण सीमा के अध्वधीन, अर्थात् केवल देशी मदिरा या केवल भारत में बनी विदेशी मदिरा या दोनों, देशी मदिरा और भारत में बनी विदेशी मदिरा के ठेकों की किस्म निर्धारित करने की सुगमता होगी तथा अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा/भारत में बनी विदेशी मदिरा, जैसी भी स्थिति हो, के लिए प्रत्येक वैयक्तिक ठेके हेतु अपने जोन के कोटा में से अनुपातिक कोटा का निर्णय करेगा। भारत में निर्मित विदेशी मदिरा में भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट, आयातित विदेशी मदिरा(बी०आई०ओ०), बीयर, वाईन, साइडर और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ शामिल होंगे। आबंटन की प्रक्रिया सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) सदस्य के रूप में तथा उपायुक्त से मिलकर बनने वाली समिति, भागीदारों की उपस्थिति में, जो विभाग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली ई-निविदाओं के मूल्यांकन की तिथि पर उपस्थित होने के इच्छुक हो, संचालित की जायेगी। ठेकों के जोन का आबंटन ई-निविदाएं आमन्त्रित करते हुए किया जाएगा। उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) अपने जिले में स्थित सभी अनु०-2, अनु०-14क ठेकों, उप-ठेकों तथा अनुमत कक्ष की भौगोलिक सूचना प्रणाली निर्देशांक को विभाग की वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

आबकारी व्यवस्था तैयार करने के बाद, जिले का उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) अपने कार्यालय, जिले के उपायुक्त के कार्यालय, जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) के साथ-साथ सम्बन्ध संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त (रेंज) कार्यालय तथा विभाग की वेबसाइट [www.haryanatax.gov.in](http://www.haryanatax.gov.in) पर आबकारी व्यवस्था को प्रदर्शित करेगा और सार्वजनिक/हितधारकों से प्रदर्शन के बाद दो दिन के लिए आपत्तियों को आमन्त्रित करेंगे और दो दिन के भीतर यदि कोई आश्रेय है तो उसका निर्णय किया जायेगा। सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) का निर्णय अन्तिम होगा।

परन्तु ठेकों के अन-अलॉटिड जोन का आबंटन, निविदाओं को आमन्त्रित करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित रीति में आरक्षित मूल्य को क्रमिक रूप से कम करके जारी रखा जाएगा :—

(i) यदि जोन की आरक्षित कीमत 5.00 करोड़ रुपये से कम है, तो मूल आरक्षित मूल्य के 5 प्रतिशत स्लेब में;

- (ii) यदि जोन की आरक्षित कीमत 5.00 करोड़ रुपये से अधिक है, तो मूल आरक्षित मूल्य के 3 प्रतिशत स्लैब में, जब तक ये आबंटित नहीं हो जाते हैं या 25 अप्रैल तक, या अगले कार्यदिवस को, यदि 25 अप्रैल को छुट्टी होती है, जो भी पहले हो और इस सम्बन्ध में आबकारी तथा कराधान आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा :

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की दशा में, पुनः आबंटन की प्रक्रिया तुरन्त विज्ञापन के माध्यम से ई-निविदाएं आमन्त्रित करते हुए प्रारम्भ की जायेंगी। पुनः आबंटन के लिए आरक्षित मूल्य शेष अवधि, जिसके लिए ठेकों का जोन मूल अनुज्ञप्ति फीस का उपयोग करते हुए पुनः आबंटित किया जाना है, के लिए अनुपातिक रूप में संगणित किया जाएगा। यदि कोई भी ई-निविदा प्राप्त नहीं हुई, तो आरक्षित मूल्य, उपर वर्णित मूल आरक्षित मूल्य का दस प्रतिशत या पचास लाख रुपये, जो भी कम हो, से घटाते हुए होगा और आमन्त्रित ई-निविदा की प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी जब तक ठेकों के जोन का पुनः आबंटन नहीं हो जाता है। यह पुनः आबंटन मूल अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम और लागत पर किया जाएगा।”;

- (ii) उक्त नियमों में, नियम 36-क में, उप-नियम (3) का लोप कर दिया जायेगा ;

- (iii) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(4) प्रत्येक बोलीदाता को उसकी बोली के साथ अग्रिम धन देना होगा। अग्रिम धन केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में भुगतानयोग्य होगा। बैंक ड्राफ्ट आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा, पंचकुला के पक्ष में भुगतानयोग्य होगा। अग्रिम धन की राशि निम्न अनुसार होगी :-

क्रम संख्या	जोन का आरक्षित मूल्य	अग्रिम धन
(i)	₹3 करोड़ से कम	₹10 लाख
(ii)	₹3 करोड़ तथा अधिक किन्तु ₹5 करोड़ से कम	₹20 लाख
(iii)	₹5 करोड़ तथा अधिक किन्तु ₹10 करोड़ से कम	₹40 लाख
(iv)	₹10 करोड़ तथा अधिक किन्तु ₹25 करोड़ से कम	₹60 लाख
(v)	₹25 करोड़ तथा अधिक	₹80 लाख।”;

- (iv) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(5) बोलीदाता को प्रत्येक जोन के लिए ₹50,000 की भागीदारी फीस जमा करानी होगी। भागीदारी फीस वापसी-योग्य नहीं है तथा समायोजनयोग्य नहीं है। भागीदारी फीस उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पक्ष में या तो नकदी में या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय में जमा की जाएगी।”;

- (v) उप-नियम (17) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(17) अनुज्ञप्तिधारी जिसको देशी मदिरा (अनु०-14क) या भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु०-2) का खुदरा मदिरा बाजार आबंटित किया जाता है, तो राज्य में प्रत्येक जिला में स्थित देशी मदिरा (अनु०-13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु०-1) के अनुज्ञप्त थोक बाजार से तिमाही आधार पर देशी मदिरा या भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण वार्षिक कोटा उठाने के लिए बाध्य होगा। कोटा को उठाने का अर्थ होगा देशी मदिरा (अनु०-13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु०-1) के अनुज्ञप्त थोक बाजार से मदिरा का भौतिक रूप से उठाना। देशी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण कोटा उठाना अनुज्ञप्तिधारी के लिए नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार बाध्यकर होगा :-

तिमाही	मासवार	
अप्रैल	9 प्रतिशत	25 प्रतिशत
मई	8 प्रतिशत	
जून	8 प्रतिशत	
जुलाई	7 प्रतिशत	45 प्रतिशत
अगस्त	7 प्रतिशत	
सितम्बर	6 प्रतिशत	

अक्तूबर	10 प्रतिशत	75 प्रतिशत
नवम्बर	10 प्रतिशत	
दिसम्बर	10 प्रतिशत	
जनवरी	9 प्रतिशत	100 प्रतिशत
फरवरी	8 प्रतिशत	
मार्च	8 प्रतिशत	

अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त वर्णित सूची के अनुसार उसे आबंटित कोटा का 100 प्रतिशत कोटा उठाना होगा। निर्धारित त्रैमासिक कोटा उठाने में असफल होने पर अल्प कोटा जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, अनुज्ञप्तिधारी को पिछली तिमाही का न उठाया गया कोटा अगली तिमाही में उठाना होगा।

तिमाही कोटे को उठाने के सम्बन्ध में उपबन्ध के अननुपालन में देशी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा की अपूर्ण मात्रा के लिए क्रमशः 70/- रुपये तथा 125/- रुपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से शास्ति लगाई जाएगी।

अनुज्ञप्तिधारी को अपना कोटा देसी मदिरा के लिए ₹6 प्रति प्रूफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के लिए ₹12 प्रति प्रूफ लीटर अन्तरण फीस अदा करने के बाद अन्तरण किया जाएगा जो कोटा अन्तरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे अनुरोध पर अन्तरण करने वाले लाईसैंसी के द्वारा अदा की जाएगी।”;

(vi) उप-नियम (19) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(19) कोई भी व्यक्ति, जिसको खुदरा मदिरा बाजार के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, ऐसे परिसरों में उसे स्थापित नहीं करेगा, जो मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अड्डे तथा पूजा के स्थल के मुख्य दरवाजे से ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 मीटर तथा शहरी क्षेत्रों में कम से कम 50 मीटर की दूरी पर स्थित हों। बशर्ते कि पूजा का ऐसा स्थल सरकार द्वारा अतिक्रमित जमीन पर न बनाया गया हो। बशर्ते कि पूजा का ऐसा स्थल कम से कम 400 वर्ग फुट की पक्की संरचना में बनाया गया हो। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में, खुदरा मदिरा बाजार मार्केट स्थानों में अवस्थित होंगे। तथापि, यह उपबन्ध ऐसे मामले में लागू नहीं होगा, जहां नया मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अड्डा या पूजा का स्थल पहले से स्थापित ठेके की निर्धारित दूरी सीमा में आता है।”;

(vii) उप-नियम (22) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(22) आबकारी तथा कराधान विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र और हरियाणा पर्यटन निगम/शहरी स्थानीय निकायों की भूमि में उच्च राजस्व क्षमता वाले शराब के ठेकों का प्रस्ताव/सुविधा प्रदान करेगा। तथापि, सम्बन्धित विभाग/निगम द्वारा नियत किए गए किराए का भुगतान अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा सीधे तौर पर ऐसे विभाग/कारपोरेशन को अदा किया जायेगा। उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के द्वारा मोनिटर किया जायेगा और तिमाही आधार पर इसकी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। तथापि, हरियाणा पर्यटक कम्प्लैक्सों की दशा में केवल अनु०-2 ठेके अनुज्ञात होंगे। पर्यटक कम्प्लैक्सों में अनु०-2 के साथ कोई अनुमत कक्ष नहीं खोला जाएगा।”;

(viii) उप-नियम (24) से (27) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

“(24) अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र के पॉश मार्केट या शॉपिंग माल में अपने संयुक्त ठेकों में से एक या इससे अधिक ठेकों को अवंत ग्रेड आउटलेट में परिवर्तित करेगा, जहाँ वह केवल भारत में निर्मित विदेशी शराब को बेचने का इरादा रखता है। इस प्रयोजन के लिए, शहरी क्षेत्रों के पॉश मार्केट या शॉपिंग माल में कुछ खुदरा दुकानों को आबंटित अवंत ग्रेड आउटलेट के रूप में पहचाना जाएगा। अवंत ग्रेड आउटलेट को क्षेत्र के ग्राहक-गण तथा सम्भावना को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा पहचाना जाएगा। अवंत ग्रेड आउटलेट में भारतीय विदेशी मदिरा (बोआईओ) के लिए पृथक वर्ग होगा। आधुनिक दुकानें किसी अतिरिक्त आबकारी शुल्क के बिना अर्थात् आबकारी शुल्क की दर पर अपने मूल कोटे के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त कोटे को उठाने के लिए हकदार होगा :

परन्तु मशीन द्वारा तैयार बिल का प्रोविजन सभी खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों के लिए बिल जारी करने के लिए आवश्यक होगा। भारत में बनी विदेशी शराब तथा देशी शराब के लिए अलग पॉस मशीनें सभी खुदरा विक्रेताओं के बिक्री काउंटर पर स्थापित की जाएंगी। इस प्रोविजन की उल्लंघना की दशा में, सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) जांच करने के बाद प्रत्येक मामले पर ₹5000 की शास्ति अनुज्ञप्तिधारी पर लगायी जायेगी। आगे उपबन्धित किया जाता है कि यदि ₹15 करोड़ के बराबर या अधिक की अनुज्ञप्ति फीस वाले शहरी क्षेत्र का कोई अनु०-2 अनुज्ञप्तिधारी ठेके के आबंटन के बाद अवंत ग्रेड आउटलेट में

अपने ठेके को बदलना चाहता है, तो उसे विभाग के अनुमोदन से ऐसा करने के लिए अनुज्ञापि किया जा सकता है। ऐसे आवेदनों को जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (विक्रय कर) तथा दो वरिष्ठतम आबकारी तथा कराधान अधिकारियों से मिलकर बनी समिति द्वारा परीक्षित किया जाएगा तथा अनुमोदन के लिए विचारा जाएगा।

“(25) खुदरा ठेकों के जोन के प्रत्येक सफल आबंटिती के लिए जोन के ठेकों की वार्षिक अनुज्ञापि फीस के 20 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी, जिसमें से अनुज्ञापि फीस का 5 प्रतिशत ई-बोली के मुल्यांकन के दिन को; अनुज्ञापि फीस का 5 प्रतिशत आबंटन के दिन के सात दिन के भीतर या 31 मार्च, 2020 को या से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करवाई जाएगी; तथा अनुज्ञापि फीस के 10 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 7 अप्रैल, 2020 तक जमा कराई जाएगी।

अगर बोली की कीमत जो आरक्षित मूल्य 25 प्रतिशत से अधिक है, के मामले में, बोलीदाता को जमा प्रतिभूति राशि स्लैब के अनुसार, जो राशि लागू है, के अलावा अपनी बोली राशि के 15 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। सफल बोली दाता के मामले में, उसकी बोली का 15 प्रतिशत सिस्टम द्वारा काट लिया जाएगा और 15 प्रतिशत सिक्वोरिटी के रूप में जमा किया जाएगा।

उसके बोली धन का 83 प्रतिशत मासिक किस्तों में उस द्वारा भुगतानयोग्य होगा; जो कि ठेके/समूह ठेकों के उसके प्रचालन के प्रारम्भ के मास से शुरू होने वाले प्रत्येक मास की 20 तिथि तक तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती मास तक भुगतान योग्य होगा। भुगतान मासिक किस्तों के रूप में अनुज्ञापिधारी द्वारा 83 प्रतिशत की सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने तक निरन्तर जारी रहेगा। उसकी प्रतिभूति का भाग, उसके बोली धन के 17 प्रतिशत के बराबर, उसके बोली धन के 83 प्रतिशत तक की राशि की किस्तों के भुगतान के बाद उसकी अनुज्ञापि फीस की ओर अन्त में समायोजित किया जायेगा। समायोजन उसकी बोली धन के 8.5 प्रतिशत की प्रत्येक, दो बराबर किस्तों में दो मास की अवधि में किया जाएगा।”

“(26) उसके बोली धनराशि के 3 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 15 अप्रैल, 2021 तक उसकी ओर बकाया था असंदत पाई गई किसी राशि को समायोजन करने के बाद वापस की जाएगी। यह राशि जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा वापस की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई ब्याज प्रतिभूति राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा। किस्तों की सूची निम्नलिखित प्रकार से होगी :-

मास	किस्तें (प्रतिशत अनुज्ञापि फीस के संदर्भ में)
अप्रैल	5.00
मई	10.30
जून	10.30
जुलाई	10.30
अगस्त	8.20
सितम्बर	8.20
अक्तूबर	8.20
नवम्बर	8.20
दिसम्बर	8.20
जनवरी	6.10

यदि आबंटिती/अनुज्ञापिधारी विहित समय में प्रतिभूति का सम्पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञापि स्वतः रद्द हो जाएगी तथा जमा प्रतिभूति, यदि कोई हो, जब्त हो जाएगी। किन्हीं दस किस्तों के भुगतान के लिए विहित समय का पालन करने में असफलता की दशा में, देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भुगतान की तिथि तक चूक के मास के प्रथम दिन से प्रभारित किया जाएगा।”

“(27) जोन के ठेकों की दशा में, जो वित्तीय वर्ष के चालू रहने के दौरान आबंटित/पुनः आबंटित किए गए हैं, बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति आबंटन के दिन जमा की जाएगी तथा बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति आबंटन की तिथि से दस दिन के भीतर जमा की जाएगी। ठेकों का जोन आबंटन/पुनः आबंटन की आगामी तिथि से प्रचालन में आएगा। मास, जिसमें आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है के लिए अनुज्ञापि फीस, उस मास के शेष दिनों के अनुपात में, मास की समाप्ति तक भुगतानयोग्य होगी। अनुज्ञापि फीस के 83 प्रतिशत में से शेष राशि बराबर मासिक किस्तों में जनवरी तक भुगतानयोग्य होगी, उसके बाद, उसकी प्रतिभूति अन्य आबंटनों के मामले में समायोजित की जाएगी।

यदि आबंटन या पुनः आबंटन दिसम्बर, 2020 के बाद किया जाता है, तो उसके बोली धन का 83 प्रतिशत मास की अन्तिम तिथि तक वसूल किया जाएगा, जिसमें आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है। आबंटन/पुनः आबंटन के मास के लिए किस्त को, पूर्ण मास के रूप में संगणित समझा जाएगा।

आबंटन/पुनः आबंटन 20 से पूर्व किया जाता है, तो भुगतान की तिथि 20 होगी या यदि आबंटन 20 को या बाद में किया जाता है, तो भुगतान मास के अन्तिम दिन को होगा।”।

6. उक्त नियमों में, नियम 37 में, उप नियम (31) में, खण्ड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“(v) वह एक्सपायर्ड मदिरा नहीं बेचेगा। यदि वह एक्सपायर्ड मदिरा की बिक्री करता हुआ पाया जाता है, तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को पहले अपराध के लिए ₹50,000/-, दूसरे अपराध के लिए ₹75,000/- तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए ₹1,00,000/- का जुर्माना भरेगा।”;

7. उक्त नियमों में, नियम 37 में, उप नियम (32) में, खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv) देशी मदिरा के लिए ₹7.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के सभी ब्रांडों के लिए ₹13.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹11 प्रति बल्क लीटर की दर से स्टॉक अन्तरण फीस उदगृहीत की जाएगी :

परन्तु कलक्टर (आबकारी) के अनुमोदन के बाद, मौजूदा अनुज्ञप्तिधारी को, केवल थोक अनुज्ञप्तिधारी की स्थिति में, पिछले वर्ष के अनुज्ञप्तिधारी के बचे हुए स्टॉक को अंतर-जिला हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में स्टॉक ट्रांसफर फीस देशी मदिरा के लिए ₹9.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए ₹15.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹12.00 होगी:

परन्तु यह और कि चालू वर्ष के दौरान थोक अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा छोड़े हुए स्टॉक को कलक्टर (आबकारी) के द्वारा उसी जिले के अन्य अनुज्ञप्तिधारी या दूसरे जिले के अनुज्ञप्तिधारी को भी हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में स्टॉक ट्रांसफर फीस देशी मदिरा के लिए ₹9.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में बनी विदेशी मदिरा के सभी ब्रांडों के लिए ₹15.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹12.00 होगी।

**टिप्पण :-** जहाँ वर्ष 2020-2021 के लिए आबकारी नीति में किसी भी प्रकार की मदिरा के आबकारी शुल्क की दर में वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2019-2020 के लिए आबकारी शुल्क की दर से अधिक है, दिनांक प्रथम अप्रैल, 2020 को बचे हुए स्टॉक पर अन्तर आबकारी शुल्क स्टॉक ट्रांसफर फीस के अतिरिक्त, यदि कोई हो, देय होगी।”।

8. उक्त नियमों में, नियम 38 में, उप-नियम (16क) में,-

- (i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

(क) अनु०-14क/अनु०-2 अनुज्ञप्तिधारी को दो ठेकों के बीच, दो उप-ठेकों के बीच और केवल ग्रामीण इलाकों में ठेका/उप-ठेका के बीच 2.5 किलामीटर की न्यूनतम दूरी बनाए रखनी होगी। उप-ठेका कानून के अन्य सभी प्रावधानों के अनुसार भी होगा। ठेका/उप-ठेके को अधिमानतः फिरनी पर स्थापित करना होगा, परन्तु गाँव के लाल डोरा से बाहर। मदिरा बेचने के लिए ठेकों के स्थान के सम्बन्ध में सभी प्रावधान उप-ठेकों पर भी लागू होंगे।”;

- (ii) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(छ) (क) उप-ठेका खोलने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति उप-ठेका के लिए ₹2,00,000 की नियत वार्षिक फीस की अदायगी पर प्ररूप अनु०-14क, अनु०-2/एस०वी० में अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। उप-ठेका उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की पूर्वानुमति पर जोन के कमाण्ड एरिया के भीतर खोलने की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में उप ठेकों के लिए प्रावधान नीचे वर्णित पैरा (ख), (ग) और (घ) के अनुसार लागू किया जायेगा ;

(ख) उप-ठेके 1000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक की जनसंख्या की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे;

(ग) 1000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से कम की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत के लिए उप-ठेके, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति से अनुज्ञात किए जाएंगे;

(घ) एक ठेका और एक उप-ठेका या दो उप-ठेके उस ग्राम पंचायत में अनुज्ञात किये जाएंगे, यदि ऐसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक है।”।

शेखर विद्यार्थी,  
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,  
हरियाणा।



**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 1st April, 2020

**No. 26/X-I/P.A. 1/1914/S.59/2020.-** In exercise of the powers conferred by Section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) and with reference to the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 09/X-1/P.A.1/1914/S.9/2020, dated the 28th January, 2020, I, Shekhar Vidyarthi, Excise Commissioner, Haryana, exercising the powers of Financial Commissioner hereby make the following rules further to amend the Haryana Liquor License Rules, 1970, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Liquor License (Amendment) Rules, 2020.
- (2) They shall come into force with effect from the 1st April, 2020.
2. In the Haryana Liquor License Rules, 1970 (hereinafter called the said rules), in rule 2, in the table,-  
 after class "L-1BF" and entries thereagainst, the following class and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

"L-2BF	retail sale of Imported Foreign Liquor (BIO) by the Retail Outlets of Indian Made Foreign Liquor i.e. L-2 Licensees, and Bar Licensees i.e. L-4 & L-5, L-12C & L-12G	Fixed fee	Collector	Collector."
--------	--	-----------	-----------	-------------

3. In the said rules, in rule 24,-
  - (i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-  
 "(i) for a license in form L-1,-
    - (a) ₹1.00 crore in case the annual quota of IMFL in an excise district is less than or equal to 10 lakh Proof Litre.
    - (b) ₹1.25 crore in case the annual quota of IMFL in an excise district is more than 10 lakh Proof Litre and less than or equal to 25 lakh Proof Litre.
    - (c) ₹1.50 crore in case the annual quota of IMFL in an excise district is more than 25 lakh Proof Litre and less than or equal to 50 Lakh Proof Litre.
    - (d) ₹2.00 crore in case the annual quota of IMFL in an excise district is above 50 Lakh Proof Litre.

Provided that no such license shall be issued unless a refundable security of 20 % of the total license fee of L-1 license is deposited which shall be liable to be forfeited or adjusted for any amount or penalty due under the Act.";
  - (ii) for clause (i-bb), the following clauses shall be substituted, namely:-  
 "(i-bb) for licenses in form L-4/L-5:-
    - (a) L-4/L-5 licenses granted to the hotels of 5 Star grading and above: ₹ 25,00,000

Provided that L-4/L-5 licenses shall also be granted within the area notified under Gurugram-Manesar Urban Complex Plan 2031 and also such places where Haryana State Industrial Development Corporation has developed Industrial Model Townships and Theme/Specialized Parks like Industrial Model Townships, Manesar, Industrial Model Townships, Bawal, Industrial Model Townships, Rohtak, Industrial Town Park Manesar, Technology Park, Panchkula:

Provided further that such licensees shall be allowed one main bar and three additional points, alongwith room service (L-3), without any further fee. Such licensee shall further be allowed to operate the main bar round the clock. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages. In case the licensee wishes to sub-lease one or more additional points, then a fixed fee of Rs. 10 Lakh per additional point shall be charged from such licensee. L-4/L-5 licensee bars can remain open up to 12.00 hours (Midnight). However, these licensed Bars may remain open upto 01:00 A.M in the districts of Gurugram, Faridabad and Panchkula. The timings of bars may be extended by one hour on payment of



additional annual fee of Rs. 10 Lakh. However, timing of these bar licenses, situated in the districts of Gurugram, Faridabad and Panchkula, may be further extended for another one hour (i.e. upto 03:00 A.M) on payment of additional annual fee of Rs. 10 Lakh. Sale of liquor including imported foreign liquor made through L-4/ L-5 outlets (bars) shall attract VAT @ 18 % + surcharge @ 5% on VAT.

(b) Hotels having grading of 4 Star: ₹ 22,50,000

Provided that such licensee shall be allowed one main bar and two additional points, alongwith room service (L-3), without any further fee. Such licensee shall further be allowed to operate the main bar round the clock. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages:

Provided further that L-4/L-5 license shall also be granted provisionally to a Hotel located anywhere in the State subject to the condition that the applicant shall procure star classification of 4 star and above from the Ministry of Tourism, Government of India within the financial year of grant, failing which the provisional license shall not be renewed subsequently. The licensee shall apply for the star rating within one month of obtaining the L-4/L-5 license:

(c) for Hotels having grading of 3 Star, -

Serial No.	Name of Distirct	License fee
1.	Gurugram	₹ 20,00,000
2.	Faridabad	₹ 17,00,000
3.	All other Districts	₹ 15,00,000

Provided that such licensee shall be allowed one main bar, alongwith one additional point and room service (L-3), without any further fee. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages.

Provided further that L-4/L-5 license shall also be granted to three star and above categories of star hotels located anywhere in the State. L-4/L-5 licenses may also be granted to those hotels having facilities equal to three star and above cagories, located anywhere in the State, by the Government.

Provided further that such licensee of category (a), (b) and (c) mentioned above shall also be allowed to serve liquor in functions, parties, events and meetings, held in up to three (03) of their identified and approved halls including banquet halls and ground floor lawns, sourced from the main bar, on payment of a one-time fee equal to 50% of his annual license fee.

The L-4/L-5 and L-12C licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) after getting license in the form of L-1BF subject to the payment of prescribed licensee fee, assessment fee and permit fee:

Provided that a refundable security of ₹5,00,000 Lacs shall be taken from the L-4/L-5 licensees in addition to the license fee.”;

(d) For a license in form L-4/L-5, for clause (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be subsituted namely:-

- |     |   |                               |
|-----|---|-------------------------------|
| (a) | for revenue district Gurugram   | ₹18,00,000                    |
| (b) | for district Faridabad  | ₹15,00,000                    |
| (c) | for all other districts in the State except Gurugram and Faridabad                        | ₹10,00,000                    |
| (d) | for Bar(s) operated by Haryana of Tourism Corporation.                                    | A composite fee ₹ 1,50,00,000 |
| (e) | Bars operated by Haryana Urban of Development Authority in their Gymkhana and Golf Clubs: | A composite fee ₹ 1,50,00,000 |

Provided that a composite security of ₹6,00,000 Lacs shall be taken from Haryana Tourism Corporation and Haryana Urban Development Authority in addition to the composite license fee.

Provided further that any L-4/L-5 licensee is found indulging in sale of liquor in bottles instead of pegs, sale of unaccounted liquor and sale of liquor without holograms/EALs his license shall be cancelled forthwith and the security amount shall be forfeited. Such licensee and premises shall also be debarred for holding any license under the Excise Act for a period of two years.

- (iii) (a) in clause (ii), for the figure and sign “70,00,000”, the figure and sign “1,00,00,000” shall be substituted;
- (b) clause (ii-a) shall be omitted;
- (c) clause (ii-b) shall be omitted;

- (iv) after clause (ii-b), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that no new letter of intent shall be granted to the proposed Bottling Plant till actual utilization of Extra Neutral Alcohol reaches 90% of the installed production capacity of the existing distilleries in the State. Further, no letter of intent shall be revalidated in the year 2020-21 for a proposed Bottling Plant, if the applicant fails to set up the plant within the prescribed time under the provisions of his letter of intent”.

- (v) for clause (ii-c), the following clause shall be substituted, namely :-

“(ii-c) The bottling fee on Indian Made Foreign Spirit shall be levied as under:-

		For supply within State	For supply outside State within India	Export out of India
a)	For D-2 licenses bottling their own brands	₹15.00/- per Proof Litre	₹7.50/- per Proof Litre	Nil
b)	For bottling plants bottling their own brands	₹20.00/- per Proof Litre	₹10.00/- per Proof Litre	Nil
c)	For bottling of brands not covered in (a) and (b) above and where no franchise fee is levied	₹22.00/- per Proof Litre	₹11.00/- per Proof Litre	Nil
d)	For bottling of beer by the brewers	₹8.00/- per Bulk Litre	₹4.00/- per Bulk Litre	Nil

Provided that bottling fee shall be leviable on liquor for export as well as on liquor on local consumption, if no franchise fee is levied.

- (vi) in clause (iv), for the existing proviso at the end, the following proviso shall be substituted, namely :-

“Provided that a license in form L-12A shall be granted by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) to an individual beyond possession limit for serving liquor during a day. The following categories shall apply online for grant of L-12A license:-

- (i) for serving liquor in banquet halls, farm houses, community centres, public parks/places of Haryana Sahari Vikash Pradhikarn, dharamshalas holding functions, get-togethers and marriage parties.
- (ii) for licensed hotels, restaurant and clubs for serving liquor outside their licensed premises on a temporary basis for hosting a function on a specific day.
- (iii) for individual obtaining license to serve liquor at a private place for a day, beyond the possession limit.

The commercial places like Banquet Halls, Hotels having Party Hall/Lawns shall have to mandatorily register with the Excise Department in the office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the respective district. The annual registration fee of Banquet Halls and Hotels having Party Halls/Lawns shall be as under:-

Serial No.	Location of Banquet Hall/Hotel	Annual Registration fee
1	Corporaion limit of Gurugram & Faridabad	₹40,000
2	Corporaion limit of Ambala, Hisar, Karnal, Panchkula, Panipat, Rohtak, Sonapat & Yamunanagar.	₹25,000
3	Council/Committee limit of remaining Distirct Headquarter cities	₹15,000

4	Banquet Halls/Hotels falling on National/State Highway outside the Municipal limit of a District (subject to the provision of Excise Policy and Excise rules).	₹10,000
5	Banquet Halls falling in Rural Areas (other than those specified in category 4 above)	₹5,000

The fee structure for L-12A license shall be as under:-

Serial No.	Location of Banquet Hall/Hotel	Annual Registration fee
(i)	For person serving liquor at commercial venues	₹7,500/- per day per function
(ii)	For individual serving liquor at a private place beyond the possession limit	₹1,000/- per day per function

The application for grant of L-12A license at all the commercial venues shall mention the details of caterer i.e. name and style, GSTIN, the approximate number of guests and the quantity of liquor.”.

“Provided further that in case any banquet hall/hotel is found serving liquor without a valid L-12A License, a penalty of ₹50,000/- shall be imposed for first offence, ₹1,50,000/- for second and third offences. Further, in case of subsequent violations, such banquet hall/hotel shall be debarred for grant of any excise license for a period of one year.

(vii) for clause (iv-b), the following clauses shall be substituted, namely :-

“(iv-b) for a license in form L-12C, -

- |     |                                  |                 |
|-----|----------------------------------|-----------------|
| (a) | for revenue district Gurugram    | ₹ 18,00,000/-   |
| (b) | for district Faridabad           | ₹15,00,000/-    |
| (c) | All other districts in the State | ₹ 10,00,000/-”. |
- except Gurugram and Faridabad :

Provided that L-12C licenses shall be granted to the Clubs of repute situated in the district headquarter cities, except as provided hereunder, having infrastructure and level of facilities required to meet the parameters and condition prescribed by the District Level Committee constituted for this purpose. The club having L-12C license shall be entitled to all the facilities granted to L-4/L-5 having grading of 3 star. The fee of this license shall be Rs.20 Lakh:

Provided further that a new license in the form of L-12C for residential condominium shall be allowed at district headquarter cities. The main bar shall be equivalent to the L-4/L-5 license while any additional mini club within the condominium shall also get license @ 20% of the license fee of its main bar for each such additional mini club. This will be subject to the condition that only the residents of the condominium or their guests shall be allowed to utilize this facility:

Provided further that in case of L-12C license granted to Sirhind Club, Ambala, the army official shall be allowed to utilize their quota through CSD canteen while the civilian members shall not be entitled for the liquor supplied through CSD canteen:

Provided further that any L-12C licensee is found indulging in sale of liquor in bottles instead of pegs, sale of unaccounted liquor and sale of liquor without holograms/EALs his license shall be cancelled forthwith and the security amount shall be forfeited. Such licensee and premises shall also be debarred for holding any license under the Excise Act for a period of two years.

Provided further that a refundable security of ₹5,00,000 Lacs shall be taken from the L-12C licensees in addition to the license fee.”;

(viii) for clause (iv-c) and entries thereagainst the following clauses and entries thereagainst shall be substituted namely:-

“(iv-c) for a license in form L-12CC,-

- |     |   |               |
|-----|---|---------------|
| (a) | Golf Club with the capacity<br>Up to 9 holes (with 2 sale points).  | ₹ 30,00,000/- |
| (b) | Golf Club with the capacity<br>Up to 18 holes (with 3 sale points). | ₹ 50,00,000/- |

Provided that license to serve liquor shall only be granted to Golf Clubs having facilities of 9 holes or more and they shall not be permitted as an additional point attached to any hotel or any type of bar license. The L-12CC Club bar licensee can remain open up to 12.00 hours (Midnight). However, these licensed Bars can remain open upto 01:00 A.M in the districts of Gurugram, Faridabad and Panchkula. The timings of bars can be extended by one hour on payment of additional annual fee of Rs. 10 Lakh. However, timing of these bar licenses, situated in the districts of Gurugram, Faridabad and Panchkula, can be further extended for another one hour (i.e. upto 03:00 A.M) on payment of additional annual fee of Rs. 10 Lakh.

**Note 1.**— Any additional point above the points already allowed, shall be allowed on payment of a fee equal to 20 % of the annual license fee for each such point and maximum number of three additional points per license shall be allowed.

**Note 2.**— In case of bars operated by Haryana Tourism and Haryana Urban Development Authority in their Gymkhana and Golf Clubs, they shall be allowed additional point on payment of a fee equal to ₹ 1 lakh for each such point.

Provided that a refundable security of ₹5,00,000 Lacs shall be taken from the L-12CC Club bar licensees in addition to the license fee.”;

(ix) in clause (v), for clause (i) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely :-

“(v) (i) The annual license fee for the wholesale outlet of country liquor (L-13) shall be as under:-

- (1) ₹30.00 lakh in case the annual quota of country liquor in an excise district is equal to or less than 25 lakh Proof Litre.
- (2) ₹35.00 lakh in case the annual quota of country liquor in an excise district is more than 25 Lakh and less than 50 Lakh Proof Litre.
- (3) ₹40.00 lakh in case the annual quota of country liquor in an excise district is equal to or more than 50 Lakh Proof Litre.

The licensee shall be required to deposit a refundable security amount of ₹ 10.00 lakh per L-13 outlet in the district.

(x) for clause (i-c) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-c) for a license in form L-1AB ₹ 60,00,000;”

(xi) for clause (i-e) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-e) for a license in form L-1B,-

1	In case of new License or where the annual sale from L-1B, in the year 2019-20, is equal to or less than 50 Lakh Proof Litre.	₹ 50,00,000;”
2	In case the annual sale from L-1B, in the year 2019-20, is more than 50 Lakh Proof Litre.	₹ 1,00,00,000;”

(xii) for clause (i-eeee), the following clause shall be substituted, namely :-

“(i-eeee) For a license in form L-1BF. –

- (a) The license fee for L-1BF shall be ₹1,00,00,000.
- (b) The license shall be granted by inviting online application on the departmental portal.
- (c) The applicant shall be allowed to make only one application. The applicant shall be, a wholesale licensee in the State of Haryana or any other State, or a proprietor firm or a partnership firm, or , a company registered under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) or a society registered under the relevant law or a firm registered under Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act 6 of 2009).
- (d) The applicant shall deposit an application fee of ₹2,00,000. The application fee shall be non refundable and non adjustable. The application shall also be accompanied with an earnest money of ₹10,00,000. The application shall be accompanied with documents establishing the identity of the applicant. Identity proof(s) of all the person(s), like proprietor, all the partners, directors and the authorized person, if there is any one so authorized, should be uploaded online along with the application.

- (e) All the applications which are found in order in accordance with the provisions of excise law shall be considered as eligible. The Department shall publish list of eligible applicants on its official website and, this will be treated as date of allotment of his license. The license shall be valid for a period starting from the day of grant of license or 1st April, 2020 whichever is later.
- (f) The eligible applicant shall deposit security amount equal to 25% of the license fee and additional license fee, if applicable, within a week, or such other time as may be prescribed in the notice, of the date of allotment. The earnest fee shall be adjustable towards the payment of amount of security.
- (g) The earnest money of the applicant shall be forfeited in the following cases:-
- In case the applicant furnishes any false or forged document in his application
  - In case the applicant is found guilty of indulging in any malpractice
  - If the successful applicant fails to deposit installment of security amount within seven days of the allotment.
  - If the successful applicant fails to furnish documents as he is required to submit to the department within the seven days of the allotment or for any other reason as the Excise Commissioner may think fit.
- (h) If the department considers that sufficient number of eligible applications have not been received, it shall initiate another round(s) of allotment by inviting more applications.
- (i) If excessive large number of applications are received, the Excise and Taxation Commissioner may reduce quota of all the licensees in equal amount so that the total minimum quota of all the licensees is in commensurate with the requirement of the State.
- (j) The eligible applicant shall submit all other documents as are required under the provisions of the notice, instructions and the Punjab Excise Act, 1914 and the rules framed there under.
- (k) The applicant shall be treated as licensee once he has deposited his security amount.
- (l) The successful applicant shall pay the license fee and additional license fee, if applicable, in eight monthly installments each equal to 10% of the license fee and additional license fee, if applicable. The remaining part of the license fee shall be adjusted from the 25% security amount. Each installment of license fee shall be payable by 20th of every month starting from April, 2020 to November, 2020. The balance amount from security, if any, shall be refundable after adjusting any amount due towards licensee. Interest shall be leviable for the period of delay in depositing the license fee in accordance with the provisions of retail licensees of Indian Made Foreign Liquor and Country Liquor.
- (m) The minimum quota for L-1BF License shall be fixed as under:-
- Whisky, Scotch, Rum, Vodka, Gin, Brandy etc. 10000 cases
  - Beer 7000 cases
  - Wine, Cider, Liqueur etc 3000 cases
- Provided that the licensee shall have to lift the minimum quota as mentioned above in the financial year. In case of failure to lift the minimum quota shall attract a penalty of ₹3000 per case of whisky and wine as mentioned above in (i), (iii) and ₹1500 per case of beer as mentioned above in (ii). The quota shall be monitored on quarterly basis. Penalty shall be leviable for deficient quantity of quota lifted at the end of each quarters calculated on cumulative basis. In case of shortage of quota penalized in a quarter, the same quota shall not be penalized again in any subsequent quarters(s). Each quarter shall have 25% of the annual quota of each segment. The quota of wine shall be allowed to be transferred on request to the segment of whisky to be computed in cases without any additional fees.
- (n) The licensee shall also be entitled to 'Additional Quota' which will be 50% of 'minimum quota' without any additional license fee. It will be available after exhausting his 'minimum quota'.
- (o) The assessment fee and permit fee shall be levied as under:-

Type of Liquor	Assessment fee	Permit fee
Whisky	₹200 per Proof litre	₹25 per Proof litre
Wine	₹200 per Bulk litre	₹25 per Bulk litre
Beer	₹70 per Bulk litre	₹10 per Bulk litre



- (p) VAT on Imported Foreign Liquor (BIO) shall be charged at the rate of 10% with surcharge @ 5%.
- (q) A penalty of ₹5000 per bottle, irrespective of size of bottles involved, shall be imposed on every unaccounted bottle of whisky and wine found at the L-1BF premises, or at any other premises like L-1, L-2, L-4 & L-5, L-12C, L-12G, L-10B etc. The penalty shall be imposed on the licensee in whose premises it is found. In case of Beer the penalty shall be ₹2000 per bottle irrespective of size of bottle.
- (r) A penalty of ₹7000 per Bottle shall be imposed on the stock of Whisky and Wine of Imported Foreign Liquor (BIO) found short at any licensed premises. In case of beer, a penalty of ₹3000 per Bottle shall be imposed.
- (s) The outgoing licensee of L-1BF for the year 2019-2020 may transfer quota of unsold stock of imported foreign liquor as on 31-03-2020 to any of incoming licensees for the year 2020-2021. A transfer fee shall also be levied @ ₹120 per proof litre for whisky, Scotch, Rum, Vodka, Gin and Brandy etc. and ₹120 per Bulk litre for wine and ₹50 per Bulk litre for Beer.
- (xiii) after clause (i-eeee), the following clause shall be inserted, namely :-  
“(i-eeeeee) for a license in form L-2BF. –
- (a) The license in form L-2BF shall be granted at a fixed fee.
- (b) The license in form L-2BF shall be granted as follows:-
- (i) The license in form L-2BF shall be granted to certain earmarked retail outlets of Indian Made Foreign Liquor i.e. L-2, at a fixed price which will be determined in accordance with the potential of the vend for Imported Foreign Liquor (BIO). The license fee of such retail outlets of Indian Made Foreign Liquor (L-2) shall be displayed in the excise arrangement separately and will be over and above the tender amount of the vend. Each such L-2BF shall be granted a minimum quota of Imported Foreign Liquor (BIO) in terms of cases of whisky, Beer and Wine. The minimum quota of such L-2BF shall be displayed in the excise arrangement. The security and license fee of L-2BF will be recovered in accordance with the provisions as are applicable for recovery of security and license fee of retail outlets i.e. L-2 and L-14A. The provisions of lifting of quota and penalty for non-lifting of quota in case of retail outlets of L-2 and L-14A shall apply mutatis mutandis to these L-2BF licensees. However, the penalty for short-lifting shall be ₹5000 per case for whisky & wine and ₹2000 per case for Beer.
- (ii) The license in form L-2BF shall also be granted to Retail outlets of Indian Made Foreign Liquor (L-2) of the State, other than those which are earmarked in the above mentioned (i) at the following license fee and quota:-
- (a) License fee ₹5,00,000 for minimum quota of 1000 cases comprising of 500 cases of Whisky, 350 cases of Beer and 150 cases of Wine.
- (b) The license fee of L-2BF shall be paid in lump sum in advance.
- Both the above mentioned categories of L-2BF licensees will be entitled to additional quota upto 50% of their minimum quota without any additional fee. The quota of Imported Foreign Liquor (BIO) shall be separate from quota of Indian Made Foreign Liquor.
- (iii) The license in form L-2BF shall also be granted to L-4 & L-5, L-12C & L-12G at a fixed fee of ₹2,00,000 payable in lump sum. The rates of the assessment fee and permit fee will be as under:-

Type of Liquor	Assessment fee	Permit fee
Whisky	₹75 per Proof litre	₹25 per Proof litre
Wine	₹75 per Bulk litre	₹25 per Bulk litre
Beer	₹40 per Bulk litre	₹10 per Bulk litre

## 3. In the said rules, in rule 27-A,-

- (i) in sub-rule (1), for clauses (iii) and (iv) the following clauses shall be substituted, namely:-

“(iii) The fee for license in form L-10B obtained by the nearest L-2 licensee Located in shopping malls. ₹25,00,000

provided that the L-10B licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) after getting license in the form of L-1BF subject to the payment of fixed fee of ₹2,00,000 payable in lump sum. The rates of the assessment fee and permit fee will be as under:-

Type of Liquor	Assessment fee	Permit fee
Whisky	₹75 per Proof litre	₹25 per Proof litre
Wine	₹75 per Bulk litre	₹25 per Bulk litre
Beer	₹40 per Bulk litre	₹10 per Bulk litre

- (iv) for a license in form L-10C ₹10,00,000

## 4. In the said rules, in rule 31-A, for the figure “325”, the figure “410” shall be substituted.

## 5. In the said rules, in rule 36-A,-

- (i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The allotment of vends in rural areas shall be grouped into Zones. The Command area of a Zone shall be the geographical area specified for the Zone in the Excise Arrangements. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) will be the competent authority to determine such command area as part of the Excise arrangement. The location of vends in urban areas will be fixed. The licensee shall have freedom, in the rural areas, to locate his vend(s) at any place within the command area of the Zone, subject to approval of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise). A Zone shall comprise of two retail vends in urban areas with prefixed locations; two retail vends in rural areas, with flexibility to the licensee to decide the location of these vends anywhere in his command area. The licensee shall have the flexibility to decide the type of vend i.e. Country Liquor only or Indian Made Foreign Liquor only or both Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor, subject to the overall limit of two retail vends, and the licensee shall also decide the proportionate quota out of his Zone's quota for each individual vend for Country Liquor/Indian Made Foreign Liquor as the case may be. The Indian Made Foreign Liquor shall include Indian Made Foreign Spirit, Imported Foreign Liquor (BIO), Beer, Wine, Cider and Ready to drink beverages. The process of allotment shall be conducted by a committee consisting of the Deputy Commissioner with Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) of the respective district as its members in the presence of the participants who wish to be present on the date of evaluation of e-bids to be published by the department in the newspapers. The allotment of Zone of vends shall be done by way of inviting e-bids. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall upload the Geographic Information System coordinates of all L-2, L-14A vends, sub-vends and anumat-kaksh located in his district on the web portal of the Department.

After preparing the Excise Arrangement the Deputy Excise and Taxation Commissioner Excise) of the district shall display the same in his office, office of the Deputy Commissioner of the district, office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) of the district as well as office of the Joint Excise and Taxation Commissioner (Range) concerned and on the departmental website [www.haryanatax.gov.in](http://www.haryanatax.gov.in) and shall invite the objections from the public/stakeholders for two days after the display and shall decide these objections if any within two days. The decision of the concerned Dy. Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district shall be final:

Provided that allotment of un-allotted zones of vends, the process of inviting tenders shall be continued by successively reducing the reserve price in the following manner:-

- In the slab of 5% of the original reserve price in case reserve price of the zone is less than Rs. 5.00 crore,
- In the slab of 3% of the original reserve price in case reserve price of the Zone is more than Rs.5.00 Cr. till these are allotted or up to 25th April, or the next working day in case 25th April happens to be a holiday, whichever is earlier and the decision of Excise and Taxation Commissioner in this regard shall be final:

Provided further that in case of cancellation of a license, the process of re-allotment shall be initiated by inviting e-bids through advertisement immediately. The reserve price for re-allotment shall be computed proportionately for the remaining period for which the Zone of vends is to be re-allotted



using the original license fee. In case no bid is received, the reserve price shall be further reduced by 10 % of the above mentioned original reserve price or Rs. 50 lac, whichever is lower and the process of inviting e-bids shall be repeated till the Zone of vends is re-allotted. This re-allotment shall be done at the risk and cost of original licensee.”.

(ii) In the said rules, in rule 36-A-, sub-rule (3), shall be omitted.

(iii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) Each bidder shall have to furnish the earnest money alongwith his bids. The Earnest Money shall be payable in the form of bank drafts only. The bank drafts shall be payable in favour of the Excise and Taxation Commissioner, Haryana, Panchkula. The amount of Earnest Money shall be as under:-

Sr. No.	Reserve Price of Zone	Earnest Money
(i)	Less than ₹3 crore	₹10 lakh
(ii)	₹3 crore and above but less than ₹5 crore	₹20 lakh
(iii)	₹5 crore and above but less than ₹10 crore	₹40 lakh
(vi)	₹10 crore and above but less than ₹25 crore	₹60 lakh
(v)	₹25 crore and above	₹80 lakh

(iv) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(5) The bidder shall have to deposit a participation fee of ₹50,000 for each Zone. The participation fee is non refundable and non adjustable. The participation fee shall be deposited in the Office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned either in cash or by demand draft in favour of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) .”.

(v) In sub-rule (17), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(17) The licensee to whom a retail liquor outlet of country liquor (L-14A) or Indian Made Foreign Liquor (L-2) is allotted, shall be bound to lift its entire annual quota of Country Liquor or Indian Made Foreign Liquor on quarterly basis from the licensed wholesale outlet of Country Liquor (L-13) and licensed wholesale outlet of Indian Made Foreign Liquor (L-1) located at every district in the State. The lifting of quota shall mean physical lifting of liquor from the licensed wholesale outlet of Country Liquor (L-13) and licensed wholesale outlet of Indian Made Foreign Liquor (L-1). It shall be obligatory for a licensee to lift entire basic quota of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor to his/ her Zone of vends as per the schedule below:-

Quarter	Month-wise	
April	9%	25%
May	8%	
June	8%	
July	7%	45%
August	7%	
September	6%	
October	10%	75%
November	10%	
December	10%	
January	9%	100%
February	8%	
March	8%	

The licensee shall have to lift 100% of the quota allocated to him as per the schedule described above. Failure to lift prescribed quarterly quota shall attract short quota penalty. Further, the licensee shall have to lift the unlifted quota of previous quarter in the next quarter.

Non compliance of the provision regarding lifting of quarterly quota shall attract penalty at the rate of Rs.70/-and Rs.125/-per proof litre of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor respectively for the deficient quantity.

The licensee shall also be allowed to transfer his quota after paying the transfer fee of ₹ 6.00 per Proof Litre for Country Liquor and ₹12.00 per Proof Litre for Indian made foreign liquor which shall be payable by the transferor licensee at the time of making such request for transfer of quota”.

- (vi) for sub-rule (19), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(19) No person to whom a license for retail liquor outlet is granted shall establish the same on such premises as is situated at a distance of less than 100 meters in rural areas and less than 50 meters in urban areas from the main gate of a recognized school/college/main bus stand and a place of worship. Provided that such place of worship is not built upon encroached Government land. Provided further that such place of worship must have a pucca structure of at least 400 square feet.

Further, in urban areas, the retail liquor outlets may preferably be located in the market places. However, this provision shall not apply in such cases, wherever a new recognized school/college/main bus stand or a place of worship comes up in the prescribed distance limit from a vend already established.

- (vii) for sub-rule (22), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(22) The Excise and Taxation Department shall offer/facilitate setting up liquor vends having high revenue potential in Haryana Sahari Vikash Pradhikarn, Gurugram Metropolitan Development Authority, Haryana State Infrastructure and Industrial Development Corporation area and land of Haryana Tourism Corporation/Urban and Rural Local Bodies. However, the rent thereof, as decided by the concerned Department/Corporation, shall be paid by the licensees directly to such Department/Corporation. The Deputy Excise and Taxation Commissioner(Excise) shall monitor and ensure its compliance on a quarterly basis. However, in case of Haryana Tourism Complexes, only L-2 vends will be allowed. No Anumat Kaksh will be allowed with the L-2 vends in the tourist complexes.”.

- (viii) for sub- rule (24) to (27), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(24) The licensee shall convert one or more of his composite vends/sub-vends to Avant-Garde Outlet(s) in posh market or shopping mall of the urban area, where he intends to sell Indian Made Foreign Liquor only. For this purpose, some of the retail outlets in the posh markets or Shopping Malls of the Urban Areas shall be identified to be allotted as Avant-Garde Outlets. The Avant-Garde Outlets shall be identified by the department, keeping in view the clientele and potential of the area. The Avant-Garde Outlets shall have a separate section for Indian Foreign Liquor (BIO). The Avant-Garde Outlets shall be entitled to lift an additional quota up to 10% of his basic quota without any additional excise duty i.e. at the rate of excise duty as applicable to basic quota:

Provided that the provision of machine generated invoices (POS) shall be mandatory for all theretail licensees to issue an invoice on sale. Separate POS Machines for IMFL and CL shall be installed at sale counter of all the retail vends. In case of violation of this provision, a penalty of ₹ 5000 per incident shall be imposed on the licensee, after enquiry by the Deputy Excise & Taxation Commissioner (Excise) concerned. It is provided further that if any retail Licensee in urban areas having license fee of his zone equal to or above ₹15 crore, wants to convert his vend into a Avant-Garde Outlet after allotment of vends, he may be allowed to do so with the approval of the Department. Such applications may be examined and considered for approval by a committee comprising of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) and two senior most Excise and Taxation Officers of the district.”.

“(25) Every successful allottee of retail Zone of vends shall be required to deposit a security amount equal to 20% of the annual license fee of the Zone of vends, out of which, 5% of the license fee shall be deposited on the day of evaluation of e-bids; 5% of the license fee within seven days of the allotment on or before 31st March, 2020 whichever is earlier; and the remaining security equal to 10% of the license fee shall be deposited by 7th of April, 2020.

In case of bids that exceed the reserve price by more than 25%, the bidder shall have to deposit an amount equal to 15% of his bid amount in addition to the amount applicable as per Earnest money deposit slabs. In case of successful bid, 15% of his bid money shall be deducted by the system and shall be deposited as 15% security.

The 83% of his bid money shall be payable by him in monthly installments each payable by 20th of each month starting from the month of commencement of his operation of vends in their Zones, and every subsequent month. The payment shall continue till full amount of 83% is paid by the licensee by way of monthly installments. A part of his security, equal to 17% of his bid money, shall be adjusted at the end towards his license fee after the payment of installments amounting to 83% of his bid money. The adjustment shall be made over a period of last two months in two equal installments; each equal to 8.5 % of his bid money. ”.

“(26) The balance security equal to 3% of his bid money shall be refunded after adjusting any amount found outstanding or unpaid towards him by the 15th April, 2021. This amount shall be refunded by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the District. No interest of any kind shall be payable on the security amount. The schedule of instalments shall be as under:-

Month	Instalments (in terms of %age license fee)
April	5.00
May	10.30
June	10.30
July	10.30
August	8.20
September	8.20
October	8.20
November	8.20
December	8.20
January	6.10

If an allottee/ licensee fails to make the full payment of security in the prescribed time, his license shall be cancelled automatically and security deposited, if any, forfeited. In case of failure to adhere to the prescribed time for payment of any of the ten installments, interests on late payment shall be charged from the first day of the month of default till the date of payment @ 18% per annum. ”.

“(27) In case of Zone of vends which are allotted/re-allotted during the currency of the financial year, the security equal to 10% of bid money shall be deposited on the day of allotment and remaining security equal to 10% of bid money shall be deposited within ten days of the date of allotment. The Zone of vends shall come into operation from the day following the date of allotment/re-allotment. The license fee for the month in which the allotment/re-allotment is made shall be payable by the end of the month, in proportion to the remaining days of that month. The remaining amount out of 83% of the license fee shall be payable upto January in equal monthly installments. Thereafter, his security shall be adjusted as in case of other allotments.

In case the allotment or re-allotment takes place after December, 2020, the 83% of his bid money shall be recovered upto the last date of month in which it is allotted/re-allotted. The installment for the month of allotment/re-allotment shall be computed treating it as a full month.

The date of payment for the month of allotment/re-allotment shall be 20th if allotment takes place before 20th or the last day of the month if allotment takes place on or after 20th.”.

6. In the said rules, in rule 37, in sub-rule 31, after clause (iv), the following clause shall be added namely:-

“(v) he shall not sell expired liquor. In case he is found selling expired liquor, such licensee shall attract a penalty of ₹50,000/- for first offence, ₹75,000/- for second offence and ₹1,00,000/- for each subsequent offences.”.

7. In the said rules, in rule 37, in sub-rule (32), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iv) The stock transfer fee shall be levied at the rate ₹7.00 per proof litre for country liquor, ₹13 per proof liter for all brands of Indian Made Foreign Liquor and ₹11 for beer per bulk litre.”

Provided further that inter-district transfer of left over stock of the licensee of the pervious year to a current licensee shall be allowed only in case of wholesalers, after approval of the Collector (Excise). The stock transfer fee in such cases shall be ₹ 9.00 per proof litre for country liquor, ₹ 15.00 per proof litre for all brands of Indian Made Foreign Liquor and ₹ 12.00 per bulk litre for beer.

It is further provided that stock surrendered due to determination of wholesale license during the currency of the year shall also be allowed to be transferred to another licensee of the same district or to another licensee of some other district by the Collector (Excise). The stock transfer fee in such cases shall be ₹ 9.00 per proof litre for country liquor, ₹ 15.00 per proof litre for all brands of Indian Made Foreign Liquor and ₹ 12.00 per bulk litre for beer.

**Note:** Where the rate of excise duty in the Excise Policy for the year 2020-21 have been increased in case of any type of liquor over the rates of excise duty for the years 2019-20, the differential excise duty on the unsold stock as on 01.04.2020 shall be payable, in addition to the stock transfer fee, if any.

8. In the said rules, in rule 38, in sub rule (16A),-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted namely :-

“(a) L-14A/L-2 licensee shall have to maintain a minimum distance of 2.5 Kilo meters between the two vends, between the two sub-vends and between vend/sub-vend in rural areas only. The sub-vend shall also be subject to all other provisions of law. The vend/sub-vend is required to be preferably located on the ‘phirni’ but outside the Lal Dora of the Village. All the provisions with regard to location of vends shall apply to the sub-vends also.

(ii) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

- “(g) (a) For opening a sub-vend, the licensee shall have to obtain a license in form L-14A, L-2/SV on payment of fixed annual fee of ₹2,00,000/- per sub-vend in rural area. Sub-vend shall be allowed within the command area of the Zone, subject to the prior approval of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise). For sub-vends in rural areas, the provisions shall be applied as per para (b), (c) and (d) mentioned below.
- (b) Sub-vends shall be allowed for each Gram Panchayat with a population more than 1000 (as per 2011 census).
- (c) Sub-vends for a Gram Panchayat having population less than 1000 (as per 2011 census), shall be allowed with the consent of the Gram Panchayat, by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise).
- (d) One vend and one sub-vend or two sub-vends shall be allowed in a Gram Panchayat, if the population of such Gram Panchayat is more than 5000 (as per 2011 census).”.

SHEKHAR VIDYARTHI,  
Excise and Taxation Commissioner,  
Haryana.